Government have also proposed to incorporate certain conditions such as involvement of the State Government in the equity of the JV Company to the extent of 20%, setting up of a Steel Plant in the State, recruitment of manpower from the State especially from District Bastar, establishement of schools/ hospital in the area by the JV company etc. The Ministry of Mines approved the proposal on 21st March, 1996 subject to observance of the provisions of MMRD Act, 1957 and Mineral Concession Rules, 1960, observing that "the State Government, the proposed joint venture company, i.e., Bailadila Mineral Development Company Ltd. and NMDC should arrive at a uniform and agreed set of conditions for the transfer and incorporate them in an agreement or any other appropriate legal instrument".

Ministry of Mines vide their lotter dated 13.6.96 requested Government of Madhya Pradesh to inform whether NMDC has consented to the conditions that the State Government proposed to incorporate under Rule 27(3) of the MCR, 1960.

The State Government of Madhya Pradesh has requested Ministry of Steel vide their letter dated 19.6.96 and 3.8.96 to advise NMDC to send their consent on the conditions proposed by the State Government.

(b) and (c) Name of the Joint Venture Company is Bailadila Mineral Development Comapny Limited. In terms of the provisions of the Joint Venture Agreement dated 10.7.1995, National Mineral Development Corporation Limited (NMDC), and Nippon Denro Ispat Limited (NDIL) and its associates are holding 11% and 89% of the equity capital of the said joint venture company respectively.

The NMDC has informed that the authorised equity capital of BMDCL is Rs. 5 crores and the total paid-up equity captial as on 2nd September, 1996 is Rs. 10,000. The share holding pattern is as under:

Member	No. of Equity Shares held	Percentage
1. N.M.D.C Ltd.	110	11%
2. Share Holding of NDIL and its Associates		
(a) Nippon Denro Ispat Limited.	150	15%
(b) Mr. Pramod Kumar Mittal	100	10%
(c) Mr. Vivek Sett	200	20%
(d) Mr. Pramod Kumar Saraogi	150	15%
(e) Mr. Vindo Garg	150	15%
(f) Mr. Arvind Jain	140	14%

कोयला खनन के क्षेत्र में परामर्शदात्री सेवा

*512. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सेन्ट्रल माइन्स प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीट्यूट को कोयला खनन के क्षेत्र में परामर्शदात्री सेवा के लिए कोई आर्डर मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेन्ट्रल माइन्स प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीट्यूट (सी०एम०पी०डी०आई०) द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी आर्डर कितने है और ऐसे ठेकों का कुल मूल्य कितना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 1995-96 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड द्वारा भारत में कोयला खनन क्षेत्र में (लिग्नाइट सहित), कुल 18 परामर्शदात्री कार्य संबंधी आर्डर प्राप्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 240.83 लाख रुपए है। इन कार्य संबंधी आर्डरों की वर्ष-वार कुल कीमत नीचे दर्शाई गई है:—

वर्ष	परामर्शदात्री कार्य संविदा संबंधी आर्डरों की संख्या	की कीमत (लाख रुपए में)
1993-94	3	21.66
1994-95	9	79.07
1995-96	6	140.10
जोड़	18	240.83

उपर्युक्त के अलावा, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० द्वारा अप्रैल, 1995 में मैं० नेशनल डेवलपमेंट कारपोरेशन जो कि तंजानिया सरकार का एक उपक्रम है, से एक विदेशी संविदा प्राप्त किया गया था, जो कि तंजानिया में मोचुमा कोलियरी के लिए तथा तापीय विद्युत गृह के लिए एक व्यवहार्य अध्ययन रिपोर्ट तैयार किए जाने के लिए प्राप्त हुआ था। इस संविदा की कुल कीमत 2.55 मिलियन अमरीकी डालर है।

देश में क्रोमाइट अयस्क के अनुमानित भंडार

*513 **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:**
श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में क्रोमाइट अयस्क के क्षेत्र-वार अनुमानित भंडारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या क्रोमाइट की खानों को गैर-सरकारी/सरकारी क्षेत्र को पट्टे पर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है!

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में क्रोमाइट अयस्क के कुल अनुमानित निक्षेपों का राज्यवार ब्यौरा निचे दिया गया है:—

क्र०सं०	राज्य	अनुमानित कुल निक्षेप (मि० टन में)
1.	आंध्र प्रदेश	0.086
2.	बिहार	0.466
3.	कर्नाटक	1.143
4.	महाराष्ट्र	0.731
5.	मणिपुर	0.002
6.	उड़ीसा	183.395
7.	तमिलनाडु	0.261

(ख) जी, हा। क्रोमाइट खानों के खनन पट्टे, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्र के आवेदकों को ऐतिहासिक तौर पर दिये गए है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार ब्यौरे निम्न प्रकार है:—

क्र०सं०	राज्य	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	—	2	2
2.	बिहार	—	1	1
3.	कर्नाटक	6	—	6
4.	महाराष्ट्र	—	2	2
5.	मणिपुर	—	2	2
6.	उड़ीसा	11	10	21
	कुल:	17	17	34

Payment of Arrears to Sugarcane Growers in U.P.

*515. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh High Court awarded payment of arrears to sugargane growers of the State with interest under the Sugarcane Control Act;

(b) whether the High Court also reprimanded his Ministry for their inaction in the matter, together with details thereof;

(c) if so, whether Government would see that other provisions of the said Act like waiting charges, compensation for uncrushed cane are also implemented;

(d) whether arrears for Sugarcane payments in Punjab and other States would also be cleared, likewise; and

(e) details of arrears in different States?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) to (e) The High Court of Allahabad (Lucknow Bench) has passed an Interim Order in W.P. NO. 1720 (MB) of 1996, M.V. Singh vs. State of U.P. and others, directing the